RAJYA SABHA

Wednesday, the 29th August, 1990/ 7th Bhadra, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, I gave you a notice for waiving of the Question Hour because new documents surfaced on Bofors which directly implicate the Minister for Commerce, Mr. Arun Nehru, in the whole sordid deal. I would like the Government to make a statement by this evening, as early as possible. Otherwise, you allow the House to discuss it. The last two years we have been discussing Bofors and Bofors under every pretext. Now, here are documents published in the *Independent* of Bombay this morning which clearly show that Mr. Arun Nehru is involved, and the whole country has a right to know the exact position on the subject is.

MR. CHAIRMAN: As I told you, I am not giving permission to waive the Question Hour. Let us proceed with the business.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The Leader of the House should give some indication of what is going to do on this matter.

MR. CHAIRMAN: You talk to him after the Question Hour. Let the Question Hour go on.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI P. SHIV SHANKER): The Government may give their own reaction, Sir, ... (*Interruptions*) ...

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): We demand the reaction of the Government.

MR. CHAIRMAN: I said, this rule can be waived only with the permission of the Chair. The Chair is not giving the permission. The matter ends.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Please tell me how else I can raise it, The country is agitated over this matter.

MR. CHAIRMAN: There are thousands of ways in the rules. You may go through the rules. ... (*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHUWALIA: We want a reaction from this deaf-and-dumb Government. ... (*Interrruptions*)...

MR. CHAIRMAN: But that is not the question. This is not the time for it.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Let the Government come with the official version.

उत्तर प्रदेश में एस०टी०डी० सुविधायें

*281. **श्री शांति त्यागी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां अब तक एस.टी.डी. सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) कब तक इन जिलों में इसकी सुविधा कर देने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गोपेश्वर, नयी टीहरी, उत्तरकाशी, सिद्धार्थनगर फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, झांसी, सोनभद्र, महाराजगंज में अभी तक एस.टी.डी. सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

गोपेश्वर, नयी टीहरी, उत्तरकाशी, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और महाराजगंज में एस.टी.डी. सुविधा मार्च, 1991 तक प्रदान की जाएगी और शेष तेरह जिलों में आठवीं योजना अवधि के अंत तक एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जाएगी।

श्री सभापति : झांसी में बहुत दिक्कत है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, झांसी में ऐसा है कि पहले क्रास बार एक्सचेंज के इक्विपमेंट्स दिए गए थे । वहां के लोगों ने कहा इलेक्ट्रानिक करा दो इस में थोड़ा विलंब हो रहा है ।

श्री सभापति : एस. टी. डी. का मामला है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : चेंज आफ इलेक्ट्रानिक होगा ।

श्री सभापति : शुरू का एस. टी. डी. हिन्दुस्तान का तो क्रासबार से ही हुआ था ?

श्री जनेश्वर मिश्र : उसको लाया नहीं गया, रोक दिया गया ।

श्री सभापति : वहां कुछ है तो ?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैनुअल एस. टी. डी. तो है झांसी में । अभी तक नहीं थी, अब लाया गया है ।

श्री शांति त्यागी : तो अभी आपका इरादा झांसी में कुछ करने का नहीं है ? और भाई, हमारी पहली आबादी की लड़ाई से झांसी जुड़ा हुआ है ।

You have to give in your own way, but I just disturbed you because everybody is talking of Jhansi.

श्री जनेश्वर मिश्र : इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज को लाने में डेढ़-दो साल की देरी लगेगी और उसके बाद ही वहां एस. टी. डी. की सुविधा दी जाएगी ।

श्री अजीत जोगी : सर, झांसी इनके खुद के उत्तर प्रदेश का है और बहुत महत्वपूर्ण शहर है ।

श्री शांति त्यागी : सभापति जी, मैं कुछ भी न पूछूं ।

श्री सभापति : आपका तो अधिकार है ही, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, मेरी तो अनाधिकार चेष्टा थी । कुछ झांसी पर थोड़ी सी याद आ गई ।

श्री शांति त्यागी : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो यह उत्तर दिया है, उसमें यह बात स्वीकार की है कि कई महत्वपूर्ण स्थान एस. टी. डी. से अभी वंचित हैं, जो बड़े अफसोस की बात है उत्तर प्रदेश संचार प्रणाली में बहुत पिछड़ा हुआ है, एक तो वहां संचार का विस्तार बहुत कम है और दूसरी बात यह है कि जो एक्सचेंज काम कर रहे हैं, वे एक्सचेंज अधिकांश पुराने टाईप के हैं और उनकी अवधि पूरी हो चुकी है । माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस फाइनेंसियल इयर में उत्तर प्रदेश में कितने नए इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज आप निर्माण कर रहे हैं और जो पुराने एक्सचेंज हैं, जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, जो गल-सड़ चुके हैं, उनमें आप कितनों का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जितने पुराने इक्विपमेंट एक्सचेंज हैं, वे सारे के सारे बदल दिए जाएंगे । इस वर्ष कितने नए एक्सचेंज लाएंगे, यह इक्विपमेंट की अवेलएबिलिटि पर निर्भर है, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री शांति त्यागी : सभापति महोदय, दूसरा मैं यह कह रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो न्याय-पंचायतें बनी हुई हैं, उनके लिए आपकी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वहां भी न्याय-पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे । तो कृपया यह फरमाएं कि आप कब तक यह काम पूरा कर लेंगे ? इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में और जिलों में जो आपकी टेलीफोन एडवायजरी कोडीज थीं, वे भंग की जा चुकी हैं । इस बारे में भी कृपया बताएं कि कब तक वे मनोनीत की जाएंगी और क्या इसमें एम. पीज. से सलाह-मशविरा भी किया जाएगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, सवाल तो केवल उत्तर प्रदेश के एस. टी. डी. के बारे में है, लेकिन माननीय सदस्य . . . . . .

श्री सभापति : आपने ही इलेक्ट्रोनिक बांच में ला दिया । जब झांसी की बात आई तो आप इलेक्ट्रोनिक पर चले गए । क्या करूं । मैंने तो कहा था कि सवाल एस . डी. का है ।

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, एक तो देश में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उन सब में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पब्लिक टेलीफोन से जोड़ने का लक्ष्य है और हम उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करेंगे । जहां तक टेलीफोन एडवायजरी कमेटी का सवाल है, इस महीने के अंत तक नए सिरे से उसका निर्माण किया जाएगा और माननीय सदस्यों से उस पर सलाह भी ली जाएगी ।

श्री नरेश यादव : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है, क्योंकि तीन जिलों के बारे में मांग की गई थी कि कब तक यह लागू कर रहे हैं, छह जिलों के बारे में आपने बताया कि लागू कर रहे हैं और तीन जिले बचते हैं—फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और झांसी । महोदय, झांसी कितना ऐतिहासिक शहर है, यह सब को मालूम है, उत्तरप्रदेश का बहुत ऐतिहासिक महत्व का स्थान है और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी यहां से चूड़ी जाती है, इतना बड़ा कारबा है, ऐसे ही फर्रुखाबाद है । इन तीन जिलों—फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और झांसी के लिए आपने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आप इसको करेंगे । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन तीनों जिलों की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए और आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए क्या आप 1991 के अन्त तक एस. टी. डी. की फेसलिटी देने का कष्ट करेंगे ? यह मेरा "अ" प्रश्न है और "ब", यह जो टेलीकोम सर्विस है, इसमें एस. टी. डी. लगाने के बाद क्या स्थिति रहती है, यह उपभोक्ता जानता है । इसलिए मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह जो टेलीकोम सर्विस है, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार क्या करने जा रही है ताकि उपभोक्ताओं की परेशानी हल हो सके और देश के सामने जो कठिनाई आती है, वे हल हो सकें ?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने पुराने एक्सचेंज हैं और जिनकी समय-सीमा समाप्त हो गई है वे सारे बदले जायेंगे ताकि उपभोक्ताओं को सेवा देने में सहूलियत हो सके और जिन 3 जिलों के बारे में माननीय यादव जी ने पूछा है, ऐसे तो हम कह रहे हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम जरूर लगा देंगे.... **(व्यवधान)** . .

श्री सभापति : इन जिलों में भी ।

श्री जनेश्वर मिश्र : इन जिलों में भी किन हम कोशिश करेंगे 91 तो नहीं, लेकिन 92 के खत्म होते-होते इन जिलों में भी इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लग जाएं और एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध हो जाए ।

श्री सभापति : लोगों को चूड़ी में दिक्कत नहीं होगी ।

श्री जनेश्वर मिश्र : चूड़ी तो वह नहीं कहते, अगर कांच का सामान कहा होता तो अच्छा था ।

श्री राम नरेश यादव : मैं माननीय मंत्री जी से फिर कहूंगा कि इनको ध्यान में रखते हुए विचार कर लें । 1991 के अंत तक जरूर लगा दें, बहुत ही आवश्यक है वहां पर ।

श्री सभापति : अगर इन्होंने कहा है तो मान लीं ।

श्री राम नरेश यादव : नहीं, यह तो कहते हैं कि 1992 के आखिर में जाकर। फिरोजाबाद जनपद का हेडक्वार्टर भी है, झांसी भी हेडक्वार्टर है और यहां इतने दिनों से नहीं हो पाया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप विचार करेंगे कि 1991 के अंत तक जरूर लगा दें, यह हमको बता दीजिए ।

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर हमें इक्विप-मेंट समय पर मिल गए तो हम जरूर प्रयास करेंगे ।

श्री सभापति : आप प्रयास करेंगे कि इक्विपमेंट जल्दी मिल जाएं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, बुलन्दशहर नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है तथा एशिया और भारत का सबसे बड़ा एटामिक पावर प्लांट "नरोरा" यहां स्थित है । 25 टेलिफोन एक्सचेंज जिले के अंतर्गत हैं लेकिन अभी तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की सुविधा बुलंदशहर में नहीं है । मान्यवर, वहां पर 1990 में सामान भी आ गया था और वह 1990 में लगाया जाना था ।

मंत्री महोदय जांच करके बताने का कष्ट करेंगे कि क्यों नहीं लगाया गया और क्या 1990 के अंत तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज बुलंदशहर में हो सकता है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : 1990 के अंत तक नहीं हो पाएगा । आप तो और कम समय कहे हैं, माननीय यादव जी ने तो 1991 तक का समय दिया, लेकिन कोशिश यह की जाएगी कि 1992 तक जरूर लगे और अगर एक्सचेंज के इक्विप-मेंट उपलब्ध हो गए तो यह भी हो सकता है कि 1991 के अंत तक लग जाए ।

SHRI KAPIL VERMA: Sir, this STD facility is very much welcome and the plans for expansion are more welcome. But, Sir, the mechanism of STD is being misused. There are widespread complaints against the linemen and the staff below who transfer calls of those who pay them to certain numbers. There is a general complaint that subscribers, particularly those with STD facility, are receiving highly inflated bills. This is a very genuine complaint in Uttar Pradesh and proably, in other parts of the country also.

MR. CHAIRMAN: Are you suggesting that STD facility should be stopped from Allahabad and Lucknow?

SHRI KAPIL VERMA: No, not at all. But care should be taken to ensure that such irregularities are not indulged in, these dishonest practices are stopped. Even a number of Members of Parliament are receiving inflated bills, running into thousands of rupees. Something must be done about this. Has the Minister received complaints about the misuse of STD facility and inflated bills?

MR. CHAIRMAN: Will you see that at least MPs don't get inflated bills?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, एस. टी. डी. फेसिलिटी के कारण जो बिलिंग के बारे में शिकायतें आई हैं... **(व्यवधान)** ....

श्री सभापति : आप उन पर विचार करेंगे ।

श्री जनेश्वर मिश्र : वह सौ में एक से भी कम है, एक सैकड़ा से भी कम है। .... **(व्यवधान)**

श्री कपिल वर्मा : यह कम्पलेंट बहुत ज्यादा हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : उनकी जांच कराई जाती है और जांच कराने पर ज्यादातर शिकायतें गलत पाई जाती हैं। इसके लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य और उपभोक्ता दोनों इस पर एतराज करते है कि कम्प्यूटर से जो हमारी एस. टी. डी. बातें होती हैं उसको बिलिंग और रिपोर्ट आम तौर पर न दिया करें क्योंकि उससे सिक्रेसी खत्म होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बारे में सतर्क हैं कि कोई ऐसी शिकायत न हो।

श्री कपिल वर्मा : कम्प्यूटर तो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में लगते हैं, सब जगह नहीं लग सकता और वही रिकार्ड करता है, लेकिन यह कालें जनरल लाइनमैन मिला देते हैं और इसमें गड़बड़ होती है। आप आप स्टाफ से बात करेंगे, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, सब जगह जानते हैं। यह बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है कि लाइनमैन पैसा लेकर के ट्रांसफर कर देते हैं।

श्री **सभापति** : आपने इलाहाबाद, लखनऊ की बात की, वहां पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है।

कुमारी आलिया : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट एक सेंसेटिव जगह है लेकिन वहां पर आम शिकायत यह है कि टेलीफोन सुविधा बिल्कुल हैन्डआ पड़ी हुई है। यहां पर एस. एस. पी. को यह शिकायत रहती है। मुझसे उन्होंने कहा कि आप टेलीफोन कम्युनिकेशन समिति में हैं और वहां का टेलीफोन खराब चलता रहता है। दूसरे, वहां पर इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम हो गया था। क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछली सरकार ने इसे कब इलेक्ट्रोनिक्स किया ? लेकिन आज तक वहां काम शुरू नहीं हुआ है तो कार्य कब तक शुरू करवाने के लिये मेहरबानी करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदय, हमसे उत्तर प्रदेश के होम सक्रेटरी ने यह शिकायत की थी कि फैजाबाद के कलैक्टर और कप्तान से होट लाईन पर हमारी बात नहीं हो पाती और फैजाबाद में अयोध्या पड़ता है जिसका विवाद इस समय सारे देश में छिड़ा है। उसके बाद हमने आदेश दिया और वहां एक सौ-डाट का इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज एलौट हो गया है। जल्दी ही लग जायेगा और अधिकारियों से बात करने के लिये लखनऊ से होट लाईन की व्यवस्था की गयी है।

उत्तर पूर्व परिषद का राज्य स्तरीय कार्यालय

*282. **श्री नारायण कार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व परिषद की योजनाओं को क्रियान्वयन की सभी संबंधित राज्यों में निगरानी रखने के लिये उत्तर पूर्व परिषद का राज्य स्तर का कार्यालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उत्तर पूर्व परिषद द्वारा त्रिपुरा में जिस सड़क का निर्माण शुरू किया गया था उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुबोध कान्त सहाय) (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है। त्रिपुरा राज्य में सड़कों के निर्माण के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न है।